पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) जी हां।

(ख) एच० बी० जे० पाइपलाइन के माध्यम से दी जाने वाली गैस का राज्यवार आवंटन निम्नानुसार है:

(एम० एम० एस० सी० एम० डी०)

गुजरात	4.77
मध्य प्रदेश	4.20
राजस्थान	3.74
उत्तर प्रदेश	19.12
हरियाणा	2.68
दिल्ली	3.02

Financing the parks and recreational areas

1903. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER b pleased to state:

(a) whether there is any proposal to finance parks and recreational areas in cities, towns and urban habitats;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have extended any such assistance to any township in Andhra Pradesh; and

(d) if so, the details thereof

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. V. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) A proposal for introducing a Centrally Sponsored Scheme of City/ Urban Forestry has been formulated by the Ministry of Urban Affairs & Employment and has been circulated to the Ministry of Environment & Forests and the Planning Commission for comments. The proposal seeks to promote city forests, green belts, woodlots, etc., based on a partnership between Central and State Governments and certain town level reforms. In addition, under the Centrally sponsored Scheme of infrastructural development in Mega Cities, the development of parks and recreational areas can be considered by the concerned State Governments.

(c) and (d) Under the Mega Cities Scheme, an amount of Rs. 41.5 crores has been allocated to Andhra Pradesh as Central assistance during 1993-96 for undertaking various urban development programmes, including development of parks and recreational areas. The Hyderabad Urban Development Authority is the nodal agency for implementation of the Scheme.

Oil and gas search by US in eastern part of the country

1904. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the U.S. has shown its keenness for oil and gas search in the eastern part of the country;

(b) if so, whether Government have considered the proposal by leading American expert body (ESRI);

(c) if so, by when Government are likely to give their consent; and

(d) by when the agreement is likely to be reached?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BALLU): (a) Some companies from U.S. have bid in the various exploration bidding rounds.

(b) to (d) Earth Sciences and Resources Institute (ESRI), University of Utah, USA and KDMIPE, ONGC have signed an MOU on 22.03.1995 for a joint scientific study entitled "A Comprehensive Review of the Hydrocarbon Prospectivity of Bengal Basin, Onshore and Offshore India."

File destroying scam in GDA

1905. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a file-destroying scam has been going on in the land department of Ghaziabad Development Authority;

(b) if so, the details in this regards; and

(c) the action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir.

(b) and (c) The State Government of Uttar Pradesh has reported that one case of destroying of file had come to its knowledge and disciplinary action has been taken against the concerned official and he has been placed under suspension.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शापिंग सेन्टरों का आवंटन

1906. **श्री इकबाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थान-वार कुल कितने शापिंग सेन्टरों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक उपरोक्त शापिंग सेन्टरों का आवंटन नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन शापिंग सेन्टरों का आवंटन कब तक किया जायेगा और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कार्रवाई की जा रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 48 शापिंग सेन्टर बनाए हैं तथा 30.6.96 की स्थिति के अनुसार शापिंक सेन्टरों के वर्ष-वार तथा स्थान-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ख) और (ग) 19 शापिंग सेन्टरों में आवंटन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। शेष शापिंग सेन्टरों में आवंटन निम्नलिखित कारणों से सम्भव नहीं हुआ है।

(i) बिजली की अनुपलब्धता।

(ii) मुद्रा बाजार में मन्दी।

(iii) रिहायशी परिसरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु दुरुपयोग के कारण मांग में कमी।

(घ) वाणिज्यिक सम्पत्ति की बिक्री एक सतत प्रक्रिया है। अनाबंटित इकाइयों के निपटान हेतु नियमित प्रयास किए जाते हैं इसके साथ-साथ इन इकाइयों को बैंकों एम०टी०एन०एल०, डाकखानों इत्यादि को आवंटित करने के लिए सम्भावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है।

विवरण

क्र०सं०	जिला केन्द्र	स्कीम का नाम / समुदाय केन्द्र	स्थानीय शॉपिंग सेन्टर	सुविधा बाजार	
1.	1993-94	शून्य	1. राजौरी गार्डन ब्लाक-जे 2. पश्चिमपर ब्लाक-ए 3. विकासपुरी ब्लाक-3	1. विकासपुरी ब्लाक-जे	1. मीरा बाग जनता सी०एच०बी०एस 2. हिन्दुस्तान सी०एच०बी०एस० साइट-1 पश्चिम बिहार 3. पश्चिमपुरी पाकेट-बी और जी 3, 5, 5ए 4. शास्त्री पार्क 5. कोण्डली घरौली सी एस-1, सेक्टर-सी 6. दिल्ली स्कूल टीचर्स 7. प्रीत विहार सीएस-1 ब्लाक-जी 8. कोण्डली घरौली सेक्टर-बी सी